****

**प्रेस विज्ञप्ति**

**गुजरात में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर आईआईएमए की एक रिपोर्ट[[1]](#endnote-1)**

**मुख्य बातें :**

* संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नई पहलें : मोबाइल मेडिकल वैन (धनवंतरी रथ), अन्न ब्रह्म योजना, हाइड्रोजन गुब्बारा आधारित निगरानी, ​​मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष निगरानी, ​​कई सक्रिय जागरूकता अभियान, प्रवासी श्रम सहायता टीम, आवश्यक उपयोगिताओं के लिए शुल्क माफी
* 4 प्रमुख शहरों में समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित करने के सक्रिय निर्णय से समय पर उपचार और स्वास्थ्य सुधार की दर बढ़ाने में मदद मिली
* राज्य भर में पूरी तरह से लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की अबाधित रूप से आपूर्ति द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखी गई
* प्रवासियों और जिनके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं था उन बाहरी लोगों को भी नियमित रूप से राशन पहुँचाने के लिए योजनाएँ शुरू की गई
* 96 प्रतिशत कोरोना वारियर्स को आवश्यक सुरक्षात्मक सामग्री प्राप्त हुई
* गुजरात पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान उदाहरणात्मक कार्य किया
* अकेले गुजरात से ही सभी राज्यों के 26 प्रतिशत प्रवासियों को 1008 श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित घर वापस भेजा गया
* सरकार के दृष्टिकोण से ज्यादातर नागरिक संतुष्ट हैं
* सर्वेक्षण में शामिल 80% से अधिक लोगों ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री के नेतृत्व के प्रति संतोष व्यक्त किया

**पूरी रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त की जा सकती है :** <https://www.iima.ac.in/web/faculty/faculty-profiles/ranjan-kumar-ghosh>

**27 जुलाई, 2020 | अहमदाबाद**

**सारांश :**

इस रिपोर्ट का उद्देश्य गुजरात में कोविड-19 की स्थिति और गुजरात सरकार द्वारा अपनाई गई गतिशील एवं विशिष्ट प्रभावी रणनीति का अवलोकन प्रदान करना है जिससे एक चेतावनी के रूप में बताया जा सके कि इस महामारी के खत्म होने में अभी बहुत समय है। इसलिए, अभी भी पहलें तैयार और कार्यान्वित की जा रही हैं जब रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया था। चार भागों में विभाजित, यह रिपोर्ट प्राथमिक और महत्वपूर्ण अनुसंधान पर आधारित है तथा गुजरात सरकार द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डालती है। इसमें राज्य की प्रतिक्रिया पर अपनी राय का मूल्यांकन करने के लिए नागरिकों और प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के सहसा उत्पन्न नमूनों के साथ एक ऑनलाइन सर्वेक्षण द्वारा सूचना के कथानक को जोड़ा गया है। इस अध्ययन से सरकार के भविष्य के प्रकटीकरण के लिए भी सिफारिशें सामने आई हैं।

**अध्ययन से प्रमुख अंतर्दृष्टि / निष्कर्ष :**

हालांकि निष्कर्ष अधूरा है, क्योंकि कोरोना संकट अब भी जारी है और काफी बड़ा भी है, लेकिन फिर भी मूल्यांकलन में क्या मिला उस पर यहाँ एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है :

**सार्वजनिक स्वास्थ्य**

इस रिपोर्ट में घोषणा जारी करने के कुछ ही दिनों के भीतर चार शहरों में - अहमदाबाद-1200 बेड, राजकोट-250 बेड, सूरत-500 तथा वडोदरा में 250 बेड के साथ 2200 बेड के कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है। इस रिपोर्ट में निजी अस्पतालों के सहयोग से पूरे गुजरात में कोविड-19 समर्पित बेड बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है। राज्य के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए उपयोग लिए जाने वाले सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मॉडल ने सरकार को पूरे गुजरात में कोविड-19 बेड की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद की है।

गुजरात सरकार का सुरक्षा किट वितरण जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र आदि वितरित करने का अभियान प्रभावी रहा क्योंकि 96 प्रतिशत कोविड-19 वारियरों को आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्राप्त हुई।

राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया सक्रिय समग्र दृष्टिकोण काफी हद तक संक्रमण के प्रसार को रोकने में सहायक था। उदाहरण के लिए, मोबाइल मेडिकल वैन की शुरुआत, जिसे धन्वंतरी रथ भी कहा जाता है, यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहा।

इस रिपोर्ट द्वारा जो एक दिलचस्प पहलू उजागर किया गया वह है राज्य सरकार द्वारा स्वयं और समुदाय के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप लोगों की जागरूकता में सुधार हुआ है। 89 प्रतिशत लोग सोचते हैं कि सार्वजनिक रूप से थूकना अपराध है और उनमें से 81 प्रतिशत मानते हैं कि थूकना व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए।

**कानून और व्यवस्था**

इस रिपोर्ट में गुजरात पुलिस की भूमिका का विस्तार से उल्लेख किया गया है। त्वरित रूप से, पुलिस बल ने प्रवर्तन और निगरानी के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अपनी रणनीति को पूरक बनाया। ड्रोनों, हाइड्रोजन गुब्बारों, गश्त करने वाली कारों को राज्य के हर नुक्कड़ पर देखा गया। पुलिस की इस तरह की उपस्थिति नागरिकों के लिए सरकार का चेहरा बन गई। लॉकडाउन को लागू करने के अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करने के अलावा, पुलिस बल ने सामुदायिक रसोई, राशन की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नजर रखी ताकि संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सरकार की पहल पर संतोष व्यक्त किया, विशेष रूप से नागरिकों की भलाई के लिए नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित प्रशासनिक निकायों के साथ मुख्यमंत्री के सूचना संचार पर संतोष व्यक्त किया। प्रभावी सूचना संचार और समन्वय के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने इस संकट के समय में भरोसे और कुशल संचालन में मदद की।

**प्रशासन के साथ विभिन्न हितधारकों के अनुभव**

राज्य सरकार ने सभी स्तरों पर प्रशासन के साथ समन्वय में महामारी के कारण उत्पन्न कई चुनौतियों से निपटने में उचित सक्रियता दिखाई। प्रत्येक स्तर पर समुचित एवं सामरिक दृष्टिकोण महामारी को संतुलित करने में सहायक रहा।

इस रिपोर्ट में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया रणनीति को लागू करने में प्रौद्योगिकी की पूरक भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से लोगों तक पहुँचने और दैनिक गतिविधियों को संचालित करने पर। मुख्यमंत्री ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। राज्य सरकार ने लोगों से कोविड-19 से खुद को सुरक्षित करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने और उसका उपयोग करने का आग्रह किया। सर्वेक्षण में 97 प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारियों ने आरोग्य सेतु ऐप को स्थापित किया था और वे इसका इस्तेमाल कर रहे थे।

इसके अलावा, रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रतिरक्षा बूस्टर के वितरण में सक्रिय रूप से संलग्न है। औऱ यह भी कि, यह रिपोर्ट सरकार द्वारा कोविड-19 रोगियों की पहचान और उन्हें आवश्यक देखभाल के अंतर्गत रखने के लिए अपनाई गई आक्रामक परीक्षण रणनीति को रेखांकित करती है।

**प्रवासी श्रमिक**

यह रिपोर्ट श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से मजदूरों और कामगारों की भारी भीड़ को पहुँचाने के लिए संचालन की सराहना करती है। मई महीने में, 15-20 दिनों की अवधि में, गुजरात ने 14.8 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 से अधिक श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की, जो स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों, पुलिस और सामाजिक समूहों के व्यापक नेटवर्क को जुटाने के माध्यम से संभव हुई। तथ्य यह है कि गुजरात प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी तक पहुँच सकता है और भोजन एवं पानी की पर्याप्त आपूर्ति के साथ उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कर सकता है, जो लोक प्रशासन के लिए एक अध्ययन करने लायक केस है।

**भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति**

रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की सफलता पर प्रकाश डाला गया है जिसमें राज्य की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी और प्रवासियों को गुजरात के हर कोने में तथा जो लोग खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में शामिल नहीं हैं उन्हें भी आवश्यक वस्तुओं की एक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है।

गुजरात में कोविड-19 संकट के प्रबंधन पर अध्ययन के संदर्भ में, रिपोर्ट में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान और उत्तर-पूर्वी राज्यों द्वारा बेहतर क्रॉस-लर्निंग के लिए सर्वोत्तम तरीकों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य में, देश का पहला कोविड-19 क्लस्टर आगरा में संस्थागत किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन, राज्य सरकार और अग्रणी कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर कार्रवाई की गई थी।

\*\*\*\*

1. भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद (आईआईएमए) के प्रोफ़ेसर रंजन कुमार घोष और उनकी शोध टीम ने हाल ही में 'गुजरात में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन : सरकारी पहलें, नेतृत्व प्रक्रियाएँ और उनके प्रभाव को समझना' विषय पर एक रिपोर्ट प्रकाशित है। यह प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

   *मीडिया प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें :*

   **दीपक भट्ट**

   **प्रबंधक, संचार**

   दूरभाष : सेल) +91-9426229429, (कार्यालय) +91-79-7152 4683,

   ईमेल : [mngr-comm@iima.ac.in](mailto:mngr-comm@iima.ac.in)

   **मिताली नायडू**

   **कार्यकारी, जनसंपर्क**

   दूरभाष : (सेल) +91-7069074816, (कार्यालय) +91-79-7152 4684,

   ईमेल : [pr@iima.ac.in](mailto:pr@iima.ac.in) [↑](#endnote-ref-1)